मैं ही बिहार

मैं ही नीतीश कुमार

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

प्राचीन देश भारत का प्रांत बिहार अपनी प्रतिभा का लोहा अनंत काल से पूरे विश्व से मनवाता रहा है। आजादी के पूर्व में बिहार का अवलौकिक इतिहास ने बिहार को सदैव सर्वोच्च स्थान पर रखा है लेकिन आजादी के बाद कुछ वर्षो तक तो बिहार अपनी गरिमा को बचाए रहा लेकिन इसके बाद बिहार धीरे-धीरे बीमार होने लगा और स्थिति इतनी भयावह हो गई की प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में वह वेंटीलेटर पर जा पहुंचा लेकिन 2005 में बिहार की कमान नीतीश कुमार ने संभाली और इसके बाद दागदार हो चुका बिहार ने पूरे देश को संदेश दिया की यह बिहार है नीतीश कुमार का, जहां सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ पर्यटन भी भरोसा के साथ आगे बढ़ने लगा। बिहार में माहौल बदला और लोगो ने नीतीश कुमार पर इतना भरोसा किया की विपक्ष हीं बिहार से गायब हो गया और बिहार के अलावा पड़ोसी राज्य भी बिहार मॉडल की सराहना करने लगे और उम्मीद की नजरों से देखने लगे। केंद्र सरकार यूपीए की हो या राजग की नीतीश कुमार का जय जयकार होता रहा है। दोस्ती तोड़ने और जोड़ने में महारथ हासिल रखने वाले नीतीश कुमार की आखिर कौन सी बात किसको कब चुभती है और कब अच्छा लगता है, इस बात की गहनता से राजनेता के साथ-साथ बिहार की जनता भी मंथन करने में लगी है। खुद गठबंधन तोड़ने का भी रिकॉर्ड उसी प्रकार बनाया, जिस प्रकार मुख्यमंत्री बनने एवं इस्तीफा देने का बनाया। फिर एक बार बिहार में सत्ता का फेरबदल की राजनीति तुल पकड़ चुकी है, लेकिन यह बिहार है और नीतीश कुमार भी...।

बिहार में नीतीश कुमार का आज कोई ठोस विकल्प ना हीं भाजपा के पास और ना ही राजद के पास, वही दूसरी ओर कांग्रेस तो खुद विपक्ष के लायक ही बच जाए ग्लिम्ट है वैसे में बार बार गठबंधन तोड़ने और जोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार की विश्वसनीयता में कोई कमी नहीं आई है अलबत्ता भाजपा और राजद किसी भी सूरत में नीतीश कुमार के चेहरे पर राजनीति कर रहे हैं। 2022 में भाजपा से अलग होने के बाद से ही नीतीश कुमार पर पक्ष और विपक्ष हमला कर रहा है लेकिन कोई भी नेता उनका विकल्प के रूप में नहीं दिखता। आर सी पी सिंह और नीतीश कुमार के बीच दरार डालकर अलग कर दिया गया ताकि श्री कुमार मुख्यमंत्री पर दवाब की राजनीति की जा सके। बिहार प्रदेश के नालंदा जिला के कल्याण बिगहा के नीतीश कुमार आज बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका विकल्प ढूंढना विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण है। श्री कुमार का जन्म 01 मार्च 1951, बख्तियारपुर, बिहार, भारत) एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार राज्य जिसकी छवि धूमिल हो गई थी, विश्वास समाप्त हो गया था, चारो तरफ अपराध और भ्रष्टाचार का बोल बाला था। महिलाएं दिन में भी असुरक्षित थी। सड़क, अस्पताल और स्कूल की हालत जर्जर थी और पुलिस का दामन इतना दागदार हो गया था की घर वालों को भी उनपर भरोसा नहीं था। बिहार का स्लोगन जब प्रशांत किशोर ने दिया था बिहार में बाहर है, नितिशे कुमार है को लोगो ने दिल पर लिया और नरेंद्र मोदी के प्रचंड प्रचार के बाद भी बिहार में 2015 में नीतीश कुमार ने विजय प्राप्त की ओर मुख्यमंत्री का ताज पहना। नीतीश कुमार बिहार के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे जिन्होंने सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री की शपथ ली और इस्तीफा दिया वावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई विशेष कमी नहीं आई है। जनता का मन मिजाज जानने तथा सरकार की योजना धरातल पर कितना है जानना और पदाधिकारी को भी हिदायत देने के लिए सबसे अधिक यात्रा की तथा एक से बढ़कर नाम दिया। सेवा यात्रा के बाद अब राजद के साथ मिलकर समाधान यात्रा पर निकले हैं। 2005 से 2014 तक बिहार के मुख्यमंत्री और 2015 से 2017 में सीएम के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद कुछ विचार के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर एनडीए से हाथ मिला लिया लेकिन फिर 05 साल बाद 2022 में अपने अस्तित्व को समाप्त होने से बचाने के लिए राजद का दामन थाम लिया। बिहार में नीतीश कुमार ने बिहार के सभी दल के नेताओं को कैसे अपने पक्ष में किया जाए तथा कैसे उसको साइड करने का कूटनीति किया जाए इसमें सफल मुख्यमंत्री के रूप में आज भी विराजमान है। नीतीश कुमार ही बिहार हैं और बिहार हीं नीतीश कुमार हैं की स्थिति बिहार प्रदेश में कायम है। एक साल बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होना है तथा 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है और केंद्र की मोदी की नजर भी बिहार और विशेषकर नीतीश कुमार पर है और यह बात उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह और तेजस्वी यादव को ज्ञात है की चाणक्य की कूटनीति की राजनीति में बिहार में नीतीश कुमार का कोई जोड़ नहीं है। सायकिल योजना और शराबबंदी के साथ सात निश्चय की योजना ने बिहार की जनता के बीच न सिर्फ लोकप्रिय बना दिया बल्कि इकलौता नेता बना दिया। भले ही नीतीश कुमार पर गठबंधन सरकार को तोड़ने का आरोप लगता है लेकिन यह भी सत्य है की श्री कुमार ने कभी भी परिवारवाद को महत्व नहीं दिया और 2005 से 2022 तक उनके पुत्र निशांत कुमार को कभी उत्तराधिकारी के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। आज एक मुखिया बनते हीं अपनी पत्नी और पुत्र के लिए राजनीति में सभी सिद्धांत को ठोकर मार देते हैं लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए कभी अपने भाई, भतीजा और बेटा के लिए कभी पहल नहीं की यह एक सुखद संदेश के रूप में सूबे की जनता ने देखा है जिसकी वजह से नीतीश कुमार की साख बढ़ी है। जबकि अन्य दलों में परिवारवाद, जातिवाद के अलावा हर प्रकार का वाद प्रस्तुत किया जाता रहा है और सत्ता के सिंहासन के लिए किसी भी प्रकार का प्रयोग करने से गुरेज नहीं करते। आज भले ही नीतीश कुमार को भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी कोसते रहें परन्तु आज भी भाजपा की यह चाहत है कि नीतीश कुमार और बिहार का साथ बन जाए। मोदी एवं कुमार के बीच दूरियां बनी रहे इसके लिए दोनों दलों में जयचंद सक्रिय हैं और दोनों शीर्ष नेताओं को भी यह ज्ञात है की कुछ तो बात है परंतु पार्टी की मर्यादा बचाए रखने के लिए गठबंधन से अलग हैं और दोनों दलों के नेता फिर से संबंध बनाना चाहते हैं परंतु कुछ लोग अपने दल को मोदी से जोड़ना चाहते हैं। बिहारी फर्स्ट की राजनीति की शंखनाद करने वाले चिराग पासवान भीं जानते हैं की भाजपा का मोह आज भी नीतीश कुमार से कम नहीं हुआ है और अकेले दम पर बिहार की सत्ता के सिंहासन पर बैठना मुश्किल है इसी कारण से चिराग भाजपा के हनुमान की भूमिका में 2020 के चुनाव एवं 2022 के विधानसभा के उप चुनाव में भी नजर आएं। हम, लोजपा, वीआईपी और रालोसपा जैसी पार्टी के साथ सिद्धांत की राजनीति की दुहाई देने वाली वामपंथी पार्टी भी नीतीश कुमार के सामने घुटने टेक चुकी है और यह साबित हो चुका है की बिहार में नीतीश कुमार और नीतीश कुमार से बिहार है का वातावरण बना हुआ है। चुनाव का शंखनाद हो चुका है और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के चक्कर में बिहार और नीतीश कुमार दोनो को खामियाजा उठाना पड़ रहा है और नीतीश कुमार 2025 में बिहार का नेतृत्व तेजस्वी को देने के लिए तैयार हैं पर 2024 की राजनीति की समीक्षा के बाद तब तक बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं।

कंपनी-डॉक्टर-सरकार और कीमत

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

देश की बढ़ती आबादी एक विस्फोट की भूमिका में है और उसके फूटने का डर सभी को है और उसी प्रकार की तबाही दवा कंपनी की दवाओं की बढ़ती कीमत की वजह से है। देश में आबादी के साथ-साथ बीमारी भी बढ़ती जा रही है और इसी का लाभ दवा कंपनी बड़ी चतुराई के साथ डॉक्टर के साथ मिलीभगत करके सरकार को भी राजस्व का चुना लगाने की कोशिश लगातार जारी है। पेट्रोल एव डीजल के बढ़ते दाम ने आवाम का जीना हराम कर रखा है वैसे में कोरोना काल में हुई आर्थिक संकट के बीच 1 अप्रैल 2022 से आवश्यक लगभग 800 दवाएं लगभग 11 प्रतिशत बढ़ जायेगी। NPPA ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। देश में लगभग 1.6 लाख करोड़ रूपये का दवा का बाजार है वैसे में आम आदमी की सेहत का क्या हाल होगा यह सोचकर कोरोना वायरस से भी ज्यादा डर लगता है दवाओं से पड़ते बोझ का और कोरोना काल में डोलो 650MG का खेल से भी अब रहस्य उठने लगा है कि किस प्रकार दवा कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किस प्रकार का गुल खिला रही है और इससे सरकार एवं जनता के सेहत पर कितना प्रभाव पड़ रहा है समझा जा सकता है। दवा कंपनी के साथ-साथ सरकारी नीतियों में अस्पष्टता के कारण दाम बढ़ते हैं और कई गंभीर बीमारी का ईलाज के लिए दवा बनाने वाली कंपनियां 50 प्रतिशत तक का दाम बढ़ा देती हैं। प्रचार तंत्र में होने वाले खर्च को बीमार के परिजनों से वसूला जाता है और सरकार इसपर गंभीर नहीं दिखती की कैसे इस काले व्यापार पर प्रतिबंध लगे।

अजीत सिंह

बीमार को दूसरा जीवन देने वाले डॉक्टर और हॉस्पिटल में गीता का उपदेश को बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं लेकिन पैसे के लालच में गीता का संदेश सिर्फ मरीजों के परिजनों पर ही लागू होता है। 100 रुपए इंजेक्शन 2000 में मरीज को दिया जाता है और इसकी भनक तब लगती है जब मरीज के परिजन को बिल का भुगतान करना होता है। अब तो एक ही छत के नीचे दवा, पैथो जांच, एम आर आई, सिटी स्कैन के नाम पर मरीजों को आर्थिक रूप से बीमार बना दिया जाता है। वेंटीलेटर पर मर चुके मरीजों का भी इलाज होता है तथा परिजन से उसके नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है की हजारों खबरे सार्वजनिक हो चुकी हैं। सरकार दवा माफियाओं के ऊपर अंकुश लगाने एवं मरीजों को कम कीमत पर दवा की उपलब्धता के लिए जन औषधि केंद्र खोलकर सुविधा पहुंचा रहे हैं। एक ही बीमारी की सैकड़ों दवाइयां और इंजेक्शन मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और हजारों कंपनी बना रही है लेकिन जिस जिस कंपनी ने डॉक्टरों के बाजार में अपना प्रतिनिधि MR, ASM, RSM, NSM जैसे को भेजकर बिक्री के अनुसार गिफ्ट और पैकेज के दम पर उस दवा को बेहतर साबित कर दिया जाता है जिसमे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है और कुछ राशि डॉक्टर को देकर कंपनी मालामाल हो जाती है और नींबू की तरह मरीज की और उसके परिजन को निचोड़ दिया जाता है। बीमार लोगों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों बीमा कंपनी हेल्थ के योजना भी बेच रही है जिससे कुछ पैसों में मरीज का बेहतर इलाज संभव हो पाया है तो कुछ हेल्थ का बीमा कंपनी बीमा करते वक्त बहुत प्रलोभन देती है लेकिन बाद में पता चलता है की इस स्कीम में इस बीमारी को कंपनी कवर नहीं करती और बीमाधारक खुद को ठगाया हुआ महसूस करता है। निर्बाधित चिकित्सा व्यापारियों द्वारा उनके मेडिकल स्टोर और क्लीनिकों पर दवाओं की बिक्री भारत देश में, दवाओं के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और वितरण को ड्रग्स और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के तहत लाइसेंस और विनियमित किया जाता है। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956; फार्मेसी अधिनियम 1948 और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एकट 1985। जिस देश की जनता अपने लिए टॉयलेट नहीं बना सकती वह लाखों रुपए का इलाज कैसे करा पायेगी, गंभीर सवाल लिए सरकार के सामने खड़ी है। दवाओं की कीमत पर अंकुश लगाने में नाकामयाब केंद्र की सरकार के सामने भेड़ बकरी की तरह बढ़ती जनसंख्या भी चुनौती है और दवा के व्यापारी सरकार की मजबूरी को अच्छी तरह से जानते हैं जिसकी वजह से नीतियों का लाभ उठाकर डोलो 650MG का खेल को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। वैसे तो दवा कंपनी पर निगरानी रखने के लिए कई एजेंसियां हैं परन्तु भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे पदाधिकारी कंपनी के साथ मिलीभगत करके मरीजों के जीवन और सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को बदनाम कर देती है। हजारों खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं की सरकारी दवा प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हैं बाजार के दाम पर, कई पदाधिकारी जेल भी जा चुके हैं परन्तु दवा कंपनी के दमदार नेटवर्क के वजह से सबकुछ कुछ हीं दिनों में सामान्य हो जाता है। कोविड 19 के वायरस में दबा कंपनी का सच और सरकारी उदासीनता का पोल खुल चुका है और इस खेल में सभी राज्य शामिल है तो केंद्र की सरकार भी कम जिम्मेवार नही है। हद तो तब हो गया है की विभिन्न क्षेत्र के माफिया दवा कंपनी बनाकर खुद को सफेदपोश बन रहे हैं और दवा का निर्माण कराकर MR रखकर RMP डॉक्टर के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कारोबार चला रहे हैं क्योंकि स्थानीय ड्रग कंट्रोलर आसानी से कुछ लेकर शांत हो जाता है। हजारों दवा की नकली कंपनी बाजार में काम कर रही है और अब तो दवा का मेडिकल स्टोर 15% की छूट दवा के MRP पर ग्राहक को दे रहा है। वैसे में अनुमान लगा सकते हैं की दवा के मेडिकल स्टोर को कितना प्रतिशत बचता होगा और दवा की कंपनी की उस दवा पर कितनी लागत होगी? जानकार मानते हैं कई कंपनी की सैकड़ों ऐसा प्रोडक्ट है जिसमे लागत से 200% से अधिक मुनाफा है इसी वजह से कंपनी डॉक्टरों को उस दवा को लिखने के लिए विदेश का भी टूर पैकेज ऑफर में देती है। भारत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक सक्रिय और गतिशील दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देती है। 8 जनवरी 2019 को कर्नाटक के कांग्रेसी सांसद केसी रामामूर्ति ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने सरकार से ऐसी कंपनियों की जानकारी मांगी थी जो डॉक्टरों को रिश्वत देती हैं और ये भी पूछा था कि इन कंपनियों अथवा डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। इस पर तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने बताया था, 'डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स' (The Department of Pharmaceuticals & DoP) को दवा कंपनियों के खिलाफ इस तरह की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिस पर जांच जारी है। इससे स्पष्ट है कि दवा कंपनियों की इस मनमानी और अनैतिक व्यापार से सरकार भी वाकिफ है। अनैतिक व्यापार करने वाली दवा कंपनियों की सूची और उनके खिलाफ हुई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं दी गई। केवल सच पत्रिका कई स्तर पर आरटीआई व अपील दाखिल की, लेकिन उसे कंपनियों व डॉक्टरों के खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित कोई संतोषजनक जवाब आज तक नहीं मिला। दवा कंपनियों और डॉक्टरों के इस गठजोड़ को सामने लाने का प्रयास किया जाता है बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई समय पर नहीं होती।

2024 और 2025 की महाजंग

PM नरेन्द्र मोदी देश के सिंहासन पर तीसरी पारी खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं तो कई राज्यों के सिंहासन पर भी कब्जा करने की कसरत भी शुरू हो चुका है जिसमें झारखंड प्रदेश में 2024 में ही लोकसभा एवं विधानसभा दोनों चुनाव हैं और बिहार में 2025 में बिहार के सत्ता का हस्तांतरण का महाजंग होगा लेकिन उसका खेल लोकसभा चुनाव के साथ - साथ शुरू हो चुका है। एक बार फिर 10 साल बाद राजनीतिक मार्ग से भटके बिहार के CM नीतीश कुमार 2014 की तरह 2024 में PM नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए महाजंग में उतर चुके हैं तो दूसरी ओर उपेन्द्र कुशवाहा NDA में शामिल होने का जुगाड़ भी लगा चुके हैं। RCP Singh और उपेन्द्र कुशवाहा के अलग होने के साथ - साथ PK की कूटनीति कहीं नीतीश कुमार को CM के लायक भी नहीं छोड़े, वैसे में 2025 में बिहार में तेजस्वी की अगुवाई स्वीकार कर चुके CM फिर से पलटी मार दें तो अलग बात है अन्यथा 2024 एवं 2025 के महाजंग में नुकसान सिर्फ बिहार और नीतीश कुमार का होना सुनिश्चित है। 2024 एवं 2025 के महाजंग में PK की राजनीति BJP के लिए सर्वाधिक नुकसानदायक साबित होगी लेकिन सत्ता का रूख समझने वाले शाह ने PK को प्रभावित कर लिया तो बिहार में महाजंग से CM का नया चेहरा भी मिल जायेगा और पहली बार BJP को CM की कुर्सी भी हासिल हो सकती है। महाजंग में सभी दलों के योद्धा अपने लिए चुनावी अखाड़े का क्षेत्र का चयन में मशक्कत करना प्रारंभ कर चुके हैं।

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

बिहार भले ही लोकतंत्र की जननी होने का दंभ भरती है लेकिन यहा के राजनेता गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर हैं जिसकी वजह से जनता के जनादेश का भी मजाक उड़ाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में कामयाब होते हैं। आजादी के बाद से ही बिहार अपने विकास के लिए मछली की तरह छटपटा रही है और विभिन्न दलों के राजनेता जनता को मूर्ख बनाकर कोई धर्म के नाम पर तो कोई जातिवाद के नाम पर उनका वोट हासिल कर लेता है और चुनाव का महाजंग जीतकर अपनी झोली भरने लगता है। आजाद भारत के 1947 से 1990 तक कांग्रेस की सरकार तो बीच-बीच में अन्य तो 1990 से 2005 तक लालू-राबड़ी की राष्ट्रीय जनता दल की सरकार चली तो बिहार के नाम से बाहरी तो बाहरी खुद बिहारी भी अपने राज्य को बीमार समझकर पलायन करने को मजबूर हो गये। रोजगार पूर्णत: ठप हो गया, शिक्षा एवं चिकित्सा की बदहाली का आलम क्या था यह किसी से नहीं छुपा तो सुरक्षा का आलम यह था की आईएएस एवं आईपीएस तक सुरक्षित नहीं थे। 2005 फरवरी से 2023 अब तक बिहार में लगे दाग को छुड़ाने के लिए अथक परिश्रम करने वाले नीतीश कुमार ने संघर्ष तो लगातार किया और बिहार की सूरत एवं सिरत भी बदली लेकिन कुर्सी के लालच की वजह से एक ईजीनियर से मुख्यमंत्री बनने वाले श्री कुमार 2012 में पहली बार पलटी मारने में कामयाब हो गये लेकिन 2014 में लोकसभा के महाजंग में भाजपा से मिली करारी हार से बदले की भावना की वजह से राजद + कांग्रेस का दामन थामकर 2015 का विधानसभा चुनाव के महाजंग में भाजपा का अहंकार को ध्वस्त किया लेकिन कुर्सी की लालच कहें या फिर बिहार के विकास के लिए समर्पित छटपटाहट की वजह से श्री कुमार से पलटीमार बने नीतीश कुमार ने 2017 में फिर पलटी मारी और 2019 का लोकसभा चुनाव के महाजंग में भाजपा के साथ मिलकर बिहार से लोकसभा महाजंग में राजद का सफाया ही कर दिया लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के महाजंग में नीतीश कुमार 43 सीट पर सिमट गये और भाजपा 80 सीटपर जीतकर भी नीतीश कुमार को ही CM बनाया लेकिन श्री कुमार को यह टीस बना हुआ रहा कि भाजपा के कूटनीति की वजह से उनकी पार्टी का वजूद 43 पर सिमट गये। केन्द्र में शामिल होने के बाद भी आरसीपी सिंह की भाजपा से बढ़ती नजदीकियां एवं PM नरेन्द्र मोदी का बढ़ता कद एवं नीतीश कुमार की लोकप्रियता का गिरता ग्रॉफ के कारण और बड़े भाई लालू यादव के बच्चों (तेजस्वी, तेजप्रताप और मीसा भारती) के द्वारा बार-बार पलटू चाचा की उपाधि से परेशान होकर 2022 में फिर से एक बार पलटू चाचा ने भतीजों से प्रेम दिखाते हुए भाजपा को ठेंगा दिखा दिया और पलटी मारकर बिहार सरकार बना ली। CM नीतीश कुमार चुनाव जीतकर एक बार भी CM नहीं बने बल्कि बिहार विधान परिषद की सदस्यता के माध्यम से राजनीति के महाजंग में बाजीगर की भूमिका में बने रहे। राजनीति एवं कूटनीति के चाणक्य बन चुके नीतीश कुमार बिहार के ऐसे राजनेता बन गये की चुनाव के महाजंग में भले ही कोई बड़ी पार्टी बन जाये लेकिन CM हर बार नीतीश कुमार ही बनेंगे। पलटी मारते हुए वह बिहार के 08 बार CM बन चुके हैं और जिस प्रकार राजद एवं भाजपा नीतीश कुमार से प्रेम करती है वह 09वीं बार भी CM बनेंगे क्योंकि दोनों दलों के पास CM का चेहरा नहीं है और जब CM का चेहरा बनाया भी राजद एवं भाजपा ने तो बिहार की जनता ने नीतीश कुमार में ही आस्था दिखाई और पलटी मारने के बाद भी और छोटी पार्टी होने के बाद भी एकबार 2020 में अधिक सीट होने के बाद भी भाजपा ने CM बनाया तो पलटी मारते हुए सरकार बदलकर राजद के साथ सरकार बनाने के लिए 2022 में अधिक सीट होने के बाद भी राजद ने CM बनाया। गठबंधन तोड़कर सरकार बनाने के अभी एक साल भी नहीं हुए है लेकिन नीतीश कुमार राजनीतिक तनाव में स्पष्ट तौरपर पर दिख रहे हैं और उनके सामने 2024 का लोकसभा चुनाव का महाजंग है तो 2025 में बिहार विधानसभा का भी महाजंग होना तय है वैसे में बिहार की जनता (वोटर) सरकार की बार बार पलटी मारने की वजह से कंफ्यूज है की आखिरकार नीतीश कुमार 2024 एवं 2025 के महाजंग में क्या गुल खिलायेंगे और किस ओर पलटी मार लेंगे? जनता की तरह राजद एवं भाजपा भी कंफ्यूज है की आखिरकार नीतीश कुमार किस ओर करवट लेंगे क्योंकि इनको कुर्सी के लिए राजनीतिक करवट लेने में कोई परहेज नहीं है क्योकि कई बार महाजंग के बाद भी पलटी मारकर खुद भी कंफ्यूज हो चुके हैं कि उनको क्या करना है। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार को याद सदैव किया जायेगा लेकिन विकास के मार्ग को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ध्वस्त कर दिया इस दाग को भी वह छुड़ा नहीं पायेंगे। एक तरफ नीतीश कुमार के द्वारा ही राजद को दागदार कहा जाता रहा है वैसे में PK की कूटनीति एवं भाजपा की शतरंज की चाल में 2024 के लोकसभा चुनाव में महाजंग होने से पहले ही फंसते दिख रहे हैं क्योकि लोकसभा के 40 सीटों में जदयू कितनी सीट पर लड़ेगी? राजद कितनी लड़ेगी, कांग्रेस कितनी पर लड़ेगी? वामदल कितने पर लड़ेंगे और हम कितने पर लड़ेगी? वैसे में नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव में मोदी के सामने पहले ही घुटने टेक चुके हैं क्येंकि 2019 में जितने सीट पर जीते थे उतनी सीट पर उम्मीदवार भी खड़े कर पायेंगे यक्ष प्रश्न बना हुआ है। वही हाल 2025 के विधानसभा के महाजंग में भी होना तय है लेकिन पलटी मारने में माहिर नीतीश कुमार कहीं 2024 के लोकसभा के महाजंग के पहले पलटी मार गये तो राजनीति की दिशा ही बदल जायेगी।

सत्ता चलाना चाहते हैं पत्रकार

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

Media का Power जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से पत्रकार सत्ता की चाहत रखने लगे हैं और अपने अनुसार सरकार चलाना चाहते हैं। आज पत्रकारिता जनहित के सारोकार से ज्यादा पक्ष एवं विपक्ष की चाअुकारिता में मशगूल होती दिख रही है। सोसल मीडिया और YouTube पर News के बढ़ते दवाब के कारण कई पत्रकार को नौकरी छोड़कर अपना YouTube चैनल चलाना पड़ रहा है। वैसे तो कई पत्रकार हैं लेकिन रविश कुमार, प्रसून बाजपेयी, अजित अंजुम पर राजनीतिक रूप से सत्ता में दखलअंदाजी करने का आरोप लगा और Media House ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कहा जाता है कि जिसने भी PM मोदी की आलोचना की और सरकार की खराब नीतियों एवं भ्रष्टाचार पर आवाज उठाया उनको मुंह की खानी पडी और बड़ा पैकेज से हाथ धोना पड़ा है। पत्रकार राजनीति में हिस्सेदारी की चाहत रखते हैं इसलिए किसी न किसी दल का प्रवक्ता बनकर News बनाते हैं। बिहार के Youtube पर मनीष कश्यप भी राजनीतिक महत्वकांक्षा की वजह से आज NSA जैसे मुकदमा झेलने को विवश है। आज राजनीतिक दल वाले भी बिना लाईसेंस के ही Youtube पर 10-10 News चैनल बनाकर पत्रकारिता का मजाक भी बना रहे हैं और सरकार की नियमों की ध ज्जियां भी उडा रहे हैं। राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर पत्रकार भी पत्रकारिता के आड़ में राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं और देश की वास्तविक सच्चाई से आवाम को वंचित कर रहे हैं।

लोकतंत्र का चौथा स्तंभ की मान्यता रखने वाला Media अपने बढ़ते जनसरोकार के कारण Govt. चलाने की कोशिश करने लगा है जिसकी वजह से उसकी विश्वसनियता पर सवाल उठने लगे हैं। देश में आज समाचार संकलन और सरकार की नाकामी की आलोचना करने के बजाय सरकार के विभागों के लाइजनिंग के कार्यों में मशगूल है जिसकी वजह से जनता के बीच वह सच सामने नहीं आ रहा है जिसका दायित्व का निर्वहन का कार्य Media को करना होता है। देश के नामचीन पत्रकार जिसकी खबरे देश की दशा एवं दिशा दे सकती है वह कहीं न कहीं सरकार के दवाब में रहने की वजह से उन खबरों से आवाम को दूर कर रहे हैं जिससे Country की सुरक्षा हो सके। पिछले कुछ वर्षों में सोसल मीडिया के बढ़ते दवाब को देखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी कहीं न कहीं कमजोर दिख रहा है क्योंकि बिना निबंधन के ही YouTube चैनल पर News दिखाने की बढ़ती होड़ और स्वतंत्रता की वजह से प्रेस एवं पत्रकारों पर से लोगों का विश्वास उठने लगा है। एक दौर था जब सहारा इंडिया और JVG जैसे कंपनियां घर-घर में एजेंट बना दिया था उसी प्रकार बढ़ती बेरोजगारी एवं सरकार की उदासीनता की वजह से हर एक बेरोजगार अपना YouTube चैनल बनाकर News का कवरेज करना शुरू कर दिया है और यही प्रमुख वजह है की देश के दिग्गज पत्रकार भी अपना News चैनल Youtube पर बनाकर सरकार की आलोचना या फिर चमचागिरी करने में सक्रिय हैं भले ही देश एवं प्रदेश की सुरक्षा और गोपनियता भंग होती है तो हो लेकिन YouTube से होने वाली मोटी कमाई तो होगा ही। बिहार एवं तामिलनाडू के बीच आपसी सौहार्द को धूमिल करने के प्रयास की वजह से मनीष कश्यप जैसे YouTube पर पत्रकारिता करने की वजह से है। जैसे आरोप से जूझना पड़ रहा है। जिस प्रकार देश के विभिन्न शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुकुरमुत्ते की तरह निजि स्कूल एवं अस्पताल खुल रहे हैं उसी प्रकार YouTube पर News चैनल वैसे में स्वाभाविक है कि राजनीति में स्थान बनाने की कोशिश करने वाले सत्ता की गोद में बैठकर चाटुकारिता में कोई कसर नहीं छोड़ते। आजकल आम पाठक एवं दर्शक भी यह भलि-भांति जानता है कि अमुक अखबार, पत्रिका एवं टीवी चैनल का पत्रकार किस राजनीतिक दल से सारोकार रखता है। Media के माध्यम से कई राज्यसभा एवं विधान परिषद में सदस्य बने हैं जिसकी वजह से अन्य के बीच भी यह माहौल बना रहता है कि कभी न कभी दूसरों को भी मोका मिलेगा और यही कारण है की राजनीति में सत्ता की Entry के लिए Media एक दमदार आधार बनता जा रहा है। भारत के पत्रकारों को यह लगने लगा है कि देश एवं राज्य की सरकार राजनीतिक दल नहीं बल्कि वह चला रहे हैं और यही प्रमुख कारण है कि सरकार की नीतियों पर चर्चा करने वजाय धर्म और उस दल के सुप्रीम का महिमामंडन करना मुख्य उद्देश्य बनता जा रहा है। केन्द्र एवं राज्य सरकारें जिस प्रकार Media की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की लगातार कोशिश कर रही है ताकि वह Media अर्थ (Advertisement) के अभाव दम तोड़ दे और उससे भी बात न बने तो झूठे मुकदमें करवाकर उसकी सत्यता की गला घोट दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रकार की गंभीर मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि Media का काम आलोचना करना है और उसकी खबर में देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं है तो सरकार को पत्रकारों को स्वतंत्र रहने देना चाहिए। Media संगठन राजनीतिक प्रभाव बनाने के दृष्टिकोण से ही सभी दलों में एक-एक पत्रकारों को नियुक्त करती है ताकि उसको सबसे पहले खबर भी मिले और तो और कोई जुगाड़ की बात भी हो तो कोई परिश्रम नहीं करना पड़े। यह सवाल ही हे कि कोई भी पत्रकार जिस भी राजनीतिक दल का बीट देखता है वह कभी भी उस दल की गंदी नीतियों एवं दल के भीतर का घीनौना सच को नहीं दिखता और ना ही खबर छापता है। प्रतिदिन पार्टी की कार्यकर्त्ता की तरह सक्रिय रहने की कोशिश में पत्रकार रहता है और सत्तारूढ़ दल का पत्रकार सिस्टम को चलाने लगता है क्योंकि विभाग एवं उसके अधिकारियों को लगता है कि पत्रकार साहब को इग्नोर करना कहीं महंगा न पड़ जाये। आंकड़ा उठाकर देखने पर यह साबित भी हो जायेगा कि तबादले के खेल में पत्रकार अहम भूमिका का निर्वहन करता है। दल या विभाग पर प्रकाश डालने पर आपको सबकुछ साफ नजर आयेगा कि सत्ता में रहने के बाद भी विभाग एवं दल के मंत्री के पास पार्टी के कार्यकर्त्ता के बजाय वहीं पर पत्रकार बैठा मिल जायेगा क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि सरकार को चलाने में पत्रकार की भूमिका भी काफी हद तक है इससे इंकार नहीं किया जा सकता। पत्रकार आवाम से जुड़ी खबरों को उस कदर नहीं दिखाता ना ही लिखता है जितना की सरकार के मुखिया एवं उनसे जुड़े मजबूत स्तंभ को ही फोकस करता है। अपराधी बनता है उसी वक्त अगर कड़ी खबर प्रकाशित हो तो वह खुंखार बन ही नहीं सकता लेकिन जब उसका इनकाउंटर होता है तो उसकी दरिंदगी का ऐसे बखान करते हैं जैसे वह काफी आक्रोश में हैं। पुलिस भी यह मानती है कि बढ़ते अपराध एवं भ्रष्टाचार में भी पत्रकारों की भूमिका संदिग्ध होती है भले ही सामाजिक दृष्टिकोण से फजीहत होने की वजह से नेता और पदाधिकारी पत्रकारों का नाम लेने से बचते हैं। सोसल मीडिया के कारण पत्रकारों को यह लगने लगा है कि वह सरकार चलान में सक्षम है क्योकि वह दल से कहीं अधिक जानकारी रखता है तथा प्रशासनिक रसूख भी। लोकतंत्र का चौथे स्तंभ की स्वतंत्रा खतरे में है, भले ही चंद पत्रकार सरकार चलाने में सफल हों।

सजग नहीं, तो घर का न घाट की रहेगी कांग्रेस

PM के लिए 2024 में Election होने वाला है और देश के भीतर इस कुर्सी पर काबिज होने के लिए बिहार के CM को PM बनने का प्रबल इच्छा है लेकिन पहले नीतीश कुमार को PM का उम्मीदवार बनायेगा कौन अहम सवाल है। 10 साल सत्ता से दूर रही कांग्रेस आज भी PM नरेन्द्र मोदी को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकती है लेकिन PM का सपना राहुल/प्रियंका के बजाय नीतीश कुमार देख रहे हैं। बिहार में बेहतर शासन का हवाला देकर विपक्ष को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए देश के उन सभी CM और पूर्व CM से मिल रहे हैं ताकि लोग इनके सपने को पंख दे सकें, भले हीं PM बने या नहीं लेकिन विपक्ष PM का उम्मीदवार भीं बना दे। यह भी बड़ी बात होगी। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस का हौसला भी बुलंद हुआ है और वह यह गलती नहीं करेगी कि अपने घर में काबिल उम्मीदवार रहते हुए किसी को उधार में लेकर PM का उम्मीदवार बनाये। 2004 से 2014 तक गठबंधन का सरकार चलाने का अनुभव कांग्रेस को है और यह वह गलती नहीं करेगी की देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी वह PM का दाव किसी और पर खेले और परिस्थिति वश ऐसा होता भी है तो कांग्रेस न घर की रहेगी न घाट की। जहां भी गठबंधन की सरकार में कांग्रेस शामिल है वहां की मंत्रियों की राजनीतिक औकात क्या है उससे वह परिचित है तथा राहुल गाँधी की ''पदयात्रा'' एवं धार्मिक सूझ-बूझ ने कर्नाटक में प्रचंड बहुमत ने PM का मुकाबला करने के लिए खुद खड़ी है। कांग्रेस के लिए 2024 का चुनाव अभिमन्यु की चक्रव्यूह की तरह है और थोड़ी से भूल .....

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

2024 की चुनावी शंखनाद हो चुकी हैं और देश के अधिकांशत: विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तिसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए मोर्चा तो खोल दिया है लेकिन PM मोदी का मुकाबला करने की क्षमता कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य किसी भी क्षेत्रीय पार्टियों में नहीं है बावजूद इसके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए राज्य-राज्य भटक रहे हैं। देश की अधिकांशत: पार्टियां जो कभी भारतीय जनता पार्टी की हिस्सा रही हैं वही पार्टियां आज 2024 में पीएम बनने के लिए ज्यादा व्याकुल दिखती है चाहे वह ममता बनर्जी हों, उद्धव ठाकरे हों, अरबिन्द केजरीवाल या फिर नीतीश कुमार, भले ही उद्धव ठाकरे एवं ममता बनर्जी भले ही PM का चेहरा हैं नहीं कहते, लेकिन नीतीश कुमार तो PM बनने के लिए ही भाजपा का दामन छोड़ा। मोदी का मुकाबला करने वाले को पता है की उनकी राजनैतिक क्षमता उनके राज्य के अलावा दूसरे राज्यों में न के बराबर है और कांग्रेस पार्टी आज भी देश की दूसरी सबबसे बड़ी पार्टी हैं तथा राष्ट्रीय पटल पर मोदी का पूरजोर विरोध कर सकती है परन्तु अन्य विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं कांग्रेस के नेता को ही प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते? कांग्रेस को भाजपा से जितना नुकसान नहीं है उससे कई गुणा ज्यादा फजीहत उसके अपने ही दल के नेताओं एवं अन्य सहयोगियों पार्टीयों से हो रहा है। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने सबके प्यारे (पक्ष-विपक्ष) अटल बिहारी बाजपेयी के इंडिया शायनिंग और फिलगुड को हराकर सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। 2014 में मोदी के 56 ईंच ने फिर से सत्ता हासिल कर लिया अपने बूते। 60 सालों तक देश को खूब जमकर लूटा है का आरोप न सिर्फ भाजपा लगाती है बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने सभाओं में तथा चुनाव के समय में रैलियों में कांग्रेस के करतूत को उजागर करने से बाज नहीं आते लेकिन आजकल वही राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अन्य नेता प्रधानमंत्री का सपना देख रही है तथा आज भी कांग्रेस का कब्र भी यही लोग खोद रहे हैं। लगभग 06 साल NDA की अटल बाजपेयी सरकार के कार्य के बाद सिर्फ पेंशन बंद करने की वजह से केन्द्र की सरकार को खोना पड़ा। कांग्रेस की यूपीए सरकार 2004-2014 के कार्यकाल के दौरान तो हमेशा किसी न किसी घोटाले की खबरों में रही है तथा बढ़ती महंगाई पर विपक्ष का अक्रामक हमला से भी विचलीत थी। PM मनमोहन सिंह का मौन धर्म के कारण भी देश की जनता में सरकार के प्रति विश्वास नहीं रहा। कोयला घोटाला 1.86 लाख करोड़ रुपये, 2जी घोटाला 1.76 लाख करोड़ रुपये, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला 70,000 करोड़ रुपये, कामनवेल्थ घोटाला 35,000 करोड़ रुपये, स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला 1,100 करोड़ रुपये, अगस्ता वेस्ट लैंड घोटाला 3,600 करोड़ रुपये, टाट्रा ट्रक घोटाला 14 करोड़ रुपये, यूपीए सरकार के दौरान कई घोटाले हुए उसमें मात्र 7 घोटालों में देश को 4,71,714 करोड़ रुपये बंदरबांट हुए और इसी को जनमानस के बीच ले जाकर NDA ने UPA का 10 की सत्ता को उखाड़ फेंका तथा यह प्रचार किया की 56 इंच वाले मोदी को हटाना कांग्रेस के लिए नामुमकिन बनता दिख रहा है। कांग्रेस फिर एकबार अन्य दलों के कंधों पर सत्ता को पाना चाहती है लेकिन अन्य दल कांग्रेस के नेता को प्रधानमंत्री के कुर्सी पर स्वीकार करना नहीं चाहते अन्यथा अन्य दल ताल ठोक कर यह कहता है कि हम कांग्रेस के साथ हैं और उनका चुना नेता मुझे स्वीकार है परन्तु अभी भी इस मामले में संशय बना हुआ है। कांग्रेस के काल में हुए घोटाले पर तंज कसते हुए भाजपा यह दावा करती है कि अगर घोटाले नहीं हुए होते तो आज देश में बुलेट ट्रेन चल रहा होता। भाजपा यह भी ताल ठोकती है कि कांग्रेस का पाप को धोने में ही समय लग रहा है अन्यथा देश विकसित देशों में शुमार होता। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस को कमजोर की कूटनीति में लगे हुए है जिसका दो उदाहरण देश में देख सकते हैं कि कांग्रेस को सबसे अधिक कोसने वाला कन्हैय्या आज खुद कांग्रेस में है तो कांग्रेस के दो महत्वपूर्ण युवा एक मध्यप्रदेश में अलग हो गया तो दूसरा राजस्थान में अलग होने के लिए मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही अंतरकलह से जूझ रही है और इसका प्रत्यक्ष फायदा भाजपा को मिल रहा है तथा अप्रत्यक्ष अन्य दलों को। कांग्रेस पार्टी के लिए कई मामले इतने विवादस्पद हो गये कि वह हमेशा राजनीतिक दृष्टिकोण से नासूर बन चुका है जिसको कभी भी अन्य दल करोदता रहता है। शाहबानो मामले में फैसला पलटा कर राजीव गाँधी ने बड़ी भूल की थी जिसका लाभ आज भाजपा उठा रही है। राजीव गांधी 25 फरवरी 1986 को मुस्लिम महिला विधेयक पारित कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था। जिसकी वजह से इंदौर की शाहबानो के पति मो० अहमद खान ने 43 साल साथ रहने के बाद उन्हें तीन तलाक दे दिया था। राजीव गांधी ने यह फैसला मुस्लिम वोट टूटने के डर से लिया था। भले ही डॉ० मनमोहन सिंह 10 वर्ष तक लगातार India के PM बने रहे लेकिन अक्टूबर 1984 को तात्कालीन PM इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में सिखों के खिलाफ हिंसा शुरू हो गई थी। अब तक इस मामले में मुकदमे चल रहे हैं। तब सिख दंगों पर राजीव गांधी ने कहा था कि ''जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है''। इन दंगों के बाद पूरा सिख समुदाय कांग्रेस के खिलाफ हो गया, जिसकी नाराजगी अब तक बरकरार है। राजीव गाँधी ने इस बात को स्वीकार किया था दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो गांव तक सिर्फ 10 पैसे ही पहुंचते हैं अर्थात 90 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। कांग्रेस अपने बयान और गठबंधन पर सजग नहीं रही तो सत्ता से दूर ही रहेगी 2024 में।

नीतीश

ने स्वयं तोड़ा जनता में विश्वास

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

PM मोदी की तरह CM नीतीश भी बिहार के लिए कम लाडले नहीं थे लेकिन नवरत्न पदाधिकारी एवं राजनीतिक बीरबल सलाहकार की वजह से उनकी साख पर दाग लग चुका है। बिहार का विकास की जब गाथा लिखी जायेगी तब-तब CM नीतीश का भी नाम प्रतिष्ठा के साथ लिखा जायेगा लेकिन विकास कर विनाश की चर्चा होगी तब तब भी CM नीतीश कुमार पर उंगली उठेगी। बदहाल, जर्जर, बर्बाद, नासूर, गुंडाराज, माफियाराज, लचर कानून व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के चंगुल से Bihar State को बाहर निकालकर पूरे देश में बिहार की विजय गाथा को अपने दम पर आगे बढ़ाया। बेटियां न सिर्फ सायकिल से स्कूल जाने लगी बल्कि प्रतिस्पर्धा के दौर में IAS टॉपर बनने लगीं। देश में जनता दल टूटा और बिहार में जार्ज फर्नांडिस एवं नीतीश कुमार ने 1994 में समता पार्टी का गठन किया लेकिन जातिवाद के आरोप से हटकर जनता दल के शरद यादव, लोकशक्ति पार्टी और समता पार्टी का विलय करके 1999 में जनता दल यूनाईटेड का गठन किया। बिहार में कांग्रेस से हुकूमत छीनकर गरीब-गुरबों की तथा-कथित लालू-राबड़ी की सरकार 2005 नवम्बर तक चली लेकिन निरंतर संघर्ष और बिहार को विकसित करने की छटपटाहट के साथ CM बनने का ख्वाब को जनता ने साकार कर दिया। 2005 से 2013 तक बिहार तेज गति से बढ़ने लगा और कानून का वास्तव में शासन दिखने लगा लेकिन CM से PM बनने का ख्वाब ने नीतीश से CM का भी पद छीन गया। इसके बाद स्थिर बिहार अस्थिर हो गया।

18 साल में 08 बार CM पद का शपथ लेना का रिकॉड नीतीश कुमार के नाम दर्ज हैं और रिश्ता जोड़ने एवं तोड़ने के मामले में भी उनकी ख्याति विशेष है। 72 वर्षीय नीतीश कुमार और बिहार के बीच अनुनाश्रय संबंध बन चुका है लेकिन इस मिथ्या को खुद ही तोड़ने में लगे हैं CM नीतीश कुमार। नीतीश नाम का अर्थ होता है नैतिकता। प्रशांत किशोर ने कहा था कि 2024 में केन्द्र में मोदी को PM बनने के बाद बिहार में CM का चेहरा बदल जायेगा और यही डर की वजह से 09 अगस्त 2022 को CM नीतीश कुमार महागठबंन के गोद में बैठ गये। 15 साल लालू-राबड़ी की सरकार को भरपेट कोसने वाले, विभिन्न मंचों से आरोप लगाने वाले तथा लालू यादव को जेल भेजने में अहम भूमिका निभाकर बिहार की आवाम का विश्वास जीतने वाले CM नीतीश कुमार कब किस ओर पलटी मार देंगे कहना मुश्किल है। वर्त्तमान Dy. CM तेजस्वी यादव बतौर प्रतिपक्ष के नेता **बेशर्म मुख्यमंत्री** की उपाधि से नवाज चुके हैं तथा तेजप्रताप **पलटू अंकल** कहते नहीं थकते थे, लेकिन कुर्सी प्रेम की वजह से नैतिकता का गला घोंटकर दूसरी बार राजद का लालटेन को थाम लिया। बदहाल बिहार को कारगर बिहार बनाने के लिए CM नीतीश कुमार ने 2005 से 2013 तक कानून व्यवस्था, शिक्षा एवं चिकित्सा का समुचित विकास और आवाम का विश्वास जीतने के लिए आधा दर्जन से अधिक कई नाम से सूबे की सम्पूर्ण यात्रा की और लोगों के बीच सभी जातियों एवं धर्मों के बीच साख बनी। सायकिल एवं पोशाक योजना ने बिहार में बेटियों के बीच सुरक्षा का भाव जागृत किया। भ्रष्टाचार होने के बाद भी **सात निश्चय** से भी बिहार में बहुत सराहनीय कार्य हुआ और शिक्षा, पुलिस विभाग सहित अन्य विभाग में नियमित नौकरी के साथ-साथ आउटसोर्स पर लाखों लोगों की नियुक्ति से बिहार का जीवन का स्तर में बहुत हद तक सुधार हुआ। जल-जीवन-हरियाली को लेकर एवं शराबबंदी के लिए मानव श्रृंखला ने बिहार की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया और GDP भी बिहार का सुदृढ़ होने लगा। बिहार के समुचित विकास एवं लालू-राबड़ी शासन का सफाया करने के लिए 1998 में नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठजोड़ किया और केन्द्र के अटल बिहार बाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रहे तथा 2005 से 2013 तक बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे लेकिन 2014 में नरेन्द्र मोदी को PM का उम्मीदवार बनने की घोषणा के बाद ही 17 साल पुराना रिश्ता भाजपा से तोड़ लिया और इस्तीफा देकर जीतन राम माँझी को बिहार का CM बना दिया। 2014 में मोदी की सरकार केन्द्र में बनी और नैतकिता का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद एवं कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गये कि PM मोदी का सटीक जवाब लालू यादव ही दे पायेंगे लेकिन नाम के अनुसार नीतीश कुमार सही रास्ते पर चलने के लिए बने फिर 26 जुलाई 2017 को महागठबंध न से हटकर NDA में शामिल होकर CM की कुर्सी पर विराजमान हो गये। भाजपा एवं राजद दोनों को नीतश कुमार ने एहसास करा दिया की बिहार का असली चेहरा मोदी या लालू नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। 2019 में नरेन्द्र मोदी 2014 से अधिक सीट जीतकर तथा 2020 के बिहार विधानसभा में 74 सीट पर जीत हासिल की लेकिन JDU 43 सीट पर सिमट गयी और इसके लिए मोदी को ही जिम्मेवार माना तथा VIP के तीन विधायक को भाजपा में शामिल करा लेने से भीतर ही भीतर दुखी हो और अप्रत्यक्ष रूय से अपने राजनीतिक सलाहकार एवं नवरत्न अधिकारियों के कूटनीति पर भाजपा से अलग होने का मन बना लिया और 2022 में अलग भी हो गये। भाजपा ने VIP को तोड़ा तो राजद से ओवैसी के 04 विधायक मिलाकर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हो गयी। इस घटना से बिहार की जनता को नीतीश कुमार के उपर से विश्वास उठने लगा है तथा जिस प्रकार बढ़ते अपराध एवं भ्रष्टाचार पर चुप्पी साध ली उससे स्वयं नीतीश कुमार ने जनता के बीच अपना विश्वास समाप्त कर लिश है। आज बिहार में जब पूर्ण शराबबंदी हुई तो बिहार की जनता को नीतीश कुमार पर और विश्वास बढ़ा लेकिन कुछ महीने बाद ही शराबबंदी और बालू के माफियाओं पर नकेल कसने में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। CM नीतीश के चेहरा यह साबित करने लगा है कि उनके भीतर राजनीतिक अस्थिरता का वबंडर के भंवर में फंसे हुए है। यही कारण है कि बयान में भी खुद को PM बन जाते हैं और अपने प्रध ान सचिव को PM का प्रधान सचिव कहकर संबोधित करने लगे हैं। पहले RCP Singh को पार्टी से हटना, इसके बाद लव-कुश की जोड़ी के खेवनहार उपेन्द्र कुशवाहा भी अपना भविष्य अधर में देख JDU से अलग हो गये, साथ ही मुस्लिम के नामचीन नेता डॉ० मोनाजीर हसन ने भी नीतीश कुमार से खुद को अलग कर लिया। पिछले 10 साल में NDA से महागठबंधन और महागठबंधन से NDA और फिर NDA से महागठबंधन की पलटीमारने की राजनीति को बिहार की जनता ने समझ लिया तथा नीतीश कुमार न हिन्दू को खुश कर पा रहे हैं और राजद के रहते ना ही मुस्लिम को पूर्ण समर्थन हासिल करने में सक्षम हैं, वैसे में कुर्मी के वोट से PM तो दूर CM ही रह जायें गलीमत है। रामनवमी की घटना को लेकर भी हिन्दू मतदाताओं के बीच भी धर्मसंकट बना हुआ है तथा धीरेन्द्र शास्त्री के कथा के आयोजन में भी विवादस्पद बातों में फंस चुके हैं। आंख मूंदकर नवरत्नों पदाधिकारियों एवं राजनीतिक बीरबल के चक्कर में स्वयं नीतीश कुमार ने अपना विश्वास जनता के बीच जनता के दरबार में समाप्त कर चुके हैं क्योकि भ्रष्ट अधिकारी सिर्फ CM के सामने Yes बने रहते हैं इसके बाद जनता गयी भाड़ में, तो जनता ने भी इसबार मन....

JAIL

भ्रष्टाचार एवं अपराध का गढ़

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

Bihar में Jail में खेल को समझने पर आपको गुंडों से ज्यादा नफरत जेल Superintendent एवं Jailer और जेल के बड़ा बाबू से हो जायेगा। किसी भी गलत आचरण या Crime करने वाले को सुधरने की एक जगह है Jail जहां Faimly से दूर रहने के वजह से सच्चाई का एहसास होता है लेकिन जब Jail, ही Corruption, Crime करने की सीख मिलने लगे तो वह आदर्श कारा Crime का सेंटर बन जाता है। जेल में कोई चेंक बाउंस होने की वजह से, कोई धोखाधड़ी के आरोप में, कोई परीक्षा में किसी की जगह पर बैठने की वजह से कोई बिना टिकट यात्रा की वजह से, कोई चोरी-डकैती की वजह से तो कोई हत्या या हत्या की साजिश के आरोप में Jail में बंद हैं और जमानत का इंतजार कर रहे हैं। वैसे आरोपियों के साथ जिस प्रकार का प्रताड़ना एवं शोषण जेल Superintendent एवं Jailer और जेल के बड़ा बाबू के द्वारा होता है उससे कुछ आरोपी, अपराधी बन जाते हैं तथा Jail के भीतर जाकर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। jail के अंदर Mobile, Drugs के साथ अन्य आमजीवन से जुड़ी सुविधाएं रूपये के दम पर पूरी हो जाती है, भले ही उसका Service Charge तीन गुणा अधिक होती है। सरकार कारा के अंदर बंद लोगों के खाना, मनोरंजन, चिकित्सा, पूजा-पाठ की समुचित व्यवस्था करती है लेकिन सरकार से मिलने वाली राशि को जेल Superintendent एवं Jailer और जेल के बड़ा बाबू उसपर ग्रहण लगाते हैं के आरोप में हमेशा कोई न कोई Suspend होता ही है। इस खेल का अंत कब होगा?

Jail एक ऐसा जगह है जहां से मानव बुरे कर्म की सजा पाकर सामाजिक जीवन में सफल हो जाता है तो दूसरा पहलू यह भी है कि किसी भी आरोप में Jail में जाने के बाद छोटे अपराध या गलती से पकड़े जाने पर Jail में मिली यातना एवं वहां विभिन्न क्षेत्रों के Criminal के School में इनता मशगूल हो जाता है तथा वहां से बाहर निकलने का रास्ता न मिलता देख, वहां फैले Corruption, Crime से वह और बड़ा Criminal बन जाता है और Jail को अपना क्राइम का HeadQuarter बना लेता है, जिसके बाद कइ अपराध करने के बाद उसपर आरोप तक तय नहीं हो पाता क्योंकि Jail के निमयों का हवाला देकर वह बच जाता है। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिसमें यह बात प्रकाश में आई है कि बड़े संगठित गिरोह का संचालन Jail के भीतर से हो रहा है। Jail के भीतर भी कई प्रकार का गैंग है जिससे Superintendent एवं Jailer भी नहीं भिड़ना चाहते। ऐसा भी नहीं है कि इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी Jail IG को या Home department को नहीं है बल्कि सूत्रों की माने तो जांच के आंच के नाम पर मामला उपर तक सेट है। कोई ईमानदार Superintendent एवं Jailer बड़ी मुश्किल से अपनी सेवा दे पाता है और मजबूरन उसको अपमान का घूंट पीना पड़ता है। बदलते राजनीतिक दौर में जबसे राजनीति का अपराधीकरण हुआ और कई दागदार एवं अपराधी राजनेता हुए तबसे Jail से ही राजनीति को अमलीजामा पहनाया जाता है। कई ऐसे भी राजनेता हैं जो Jail में रहने के बाद भी चुनाव बहुमत से जीत जाते हैं, वैसे में Public यह समझ ही नहीं पाती कि जिस नेता का इतना जनमत है वह अपराधी कैसे हैं और अपराधी है तो फिर उसको लोग Vote कैसे करते हैं। जेल में बंद आरोपी एवं कैदी जब बाहर आते हैं और वह अपनी पीड़ा बताते हैं तथा भीतर का सच का बयान करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि सैकड़ों ऐसे अपराधी है जिनका व्यवसाय बाहर से बेहतर Jail में ही होता है और इसका Partner, जेल के Superintendent एवं Jailer तक होते हैं। Jail से Court तक कैदियों के लाने की जिम्मेवारी जिस वाहन की होती है और उसमें तैनात Officer और सिपाही की हैसियत किसी छोटे व्यापारी से कम नहीं होती और इसी च्तवपिज के चक्कर में कभी-कभार कैदी वाहन से ही फरार हो जाते हैं और सरकार एवं जनता को यह बताया जाता है कि आंख में मिर्ची झोंक दिया या बाम लगा दिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि Jail या वाहन पर कैदी के पास इस प्रकार की सामग्री कैसे पहुंचती है। Jail में बंद कैदी घंटों बात करता है और उसकी मोटी किमत चुकाता है जबकि Jail के भीतर मोबाइल एवं नशीले पदार्थ वर्जित हैं लेकिन आयदिन छापेमारी में इस प्रकार का मामला खुलकर सामने आता है। Jail में बंद कैदियों का नेटवर्क भी पुलिस एवं पत्रकारों की तरह होता है तथा वह भी कारगर सिद्ध होता है, कई बार यह भी होता है कि बंद कैदी के प्रयास से अपराध नियंत्रण में बड़ी सफलता मितली है। Jail में Newspaper एवं Magazine, Tv सहित मनोरंजन के सभी प्रकार के संसाधन सरकार मुहैय्या कराती है तथा Weekly भोजन का Menu तक रहता है लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टा है और तो और कैदियों के पैसे से Jail का संचालन होता है। किसी भी Jail में Jail के Superintendent एवं Jailer की आय से अधिक की संपत्ति की जांच होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। जब Jail में वरीय अधिकारी रूटीन जांच के लिए आते हैं उस वक्त जेल के नियमों का पालन किया जाता है तथा मानवाधिकार का भी पूरा ख्याल रखा जाता है और जब वरीय अधिकारी का औचक नीरिक्षण होता है तो Jail में चल रहे कुकर्म का भंडाफोड़ होता है और फिर जांच के नाम पर भी बड़े स्तर पर वसूली होती है। आरोपी कैदियों के लिए परिजन फल या अन्य सामग्री भी देते हैं तो द्वारपाल से लेकर वार्डन तक पहुंचते - पहुंचते वह फल अन्य सामग्री आधा से भी कम हो जाता है। Jail में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होता है बस उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और जिनका कोई जुगाड़ नहीं है उसको किसी न किसी गैंग का सहारा लेना पड़ता है जिसकी वजह से सुधरने वाला व्यक्ति या युवाओं का विश्वास कानून एवं सरकार से उठने लगता है। कैदी या आरोपी से परिजन को मिलने के लिए भी 500-1000 रूपये का नजराना देना पड़ता है तथा किसी भी प्रकार के सामग्री खरीदने पर बाजार से चार गुना ज्यादा की राशि वसूली जाती है। जमानत हो जाने पर जेल से छोड़ने के नाम पर भी मनमाना धनराशि की मांग की जाती है। बिहार एवं झारखंड के Jail की हालत बद से बद्तर है और यहां तैनात सिपाही से लेकर Superintendent एवं Jailer की संपत्ति की जांच प्रतिवर्ष होगा तब जाकर ही नकेल कसा जा सकेगा अन्यथा भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मी एवं अधिकारी अन्य लोगों के नाम से संपत्ति खरीदते हैं तथा धनराशि वसूलने के लिए अलग से Agent भी रखते हैं। सूत्रों की माने तो जिस प्रकार थाना का बोली लगता है उसी प्रकार Jail में भी यह खेल चलता है और Officer के साथ-साथ पक्ष-विपक्ष तक हिस्सा पहुंचता है और उम्र कैद की सजा काट रहे कुछ दबंग भी अपना हिस्सा हासिल करते हैं ताकि कोई इस ओर ध्यान द दें और जेल में बंद आरोपी या कैदी मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के कारण मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। जेल को सुधारगृह के नाम से जाना जाता है लेकिन आजाद भारत में शायद ही कोई जेल होगा जहां से कोई सुधरकर बाहर आया हो, भले ही वह सुधरना चाहता हो परन्तु कानून की लाचारी एवं पैसे की ताकत को उसको एहसास हो जाता है। भ्रष्टाचार की Center बनता जा रहा है Jail.

I.N.D.I.A

में भरोसा नहीं है!

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

कलियुग में सत्ता के लिए कोहराम मचा हुआ है और पूर्व PM अटल बिहारी बाजपेयी ने गठबंधन की राजनीति का मार्ग बनाकर आज सबको सत्ता बनाने के लिए जुगाड़ दे दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में PM Modi को उखाड़ फेकने का प्रयास 26 दलों को मिलाकर बना I.N.D.I.A. करने का प्रयास कर रही है। किसी भी प्रकार PM Modi को हटाने के लिए राजनीतिक दुश्मनी के बाद भी गलबहियां करने का साहसिक प्रयास जारी है, वहीं दूसरी ओर NDA में 38 दल शामिल हैं और 9 ऐसे दल हैं जो न तो I.N.D.I.A. में हैं और ना ही NDA में लेकिन PM Modi के सभी बिल धारा 370, CAA/NRC तीन तलाक, UCC तथा अन्य कई मामले में 9 दल मोदी का समर्थन करने से पीछे नहीं हटती। पटना एवं बैंगलूरू में हुई बैठक के बाद भी I.N.D.I.A. के कई दल का मित्रवत् संबंध में खटास आज भी जारी है और दिल्ली के केजरीवाल और बंगाल की ममता को कांग्रेस के क्रिया-कलाप से नाराज हैं। I.N.D.I.A. के गुट में भले ही राजनीतिजक दलों Number 26 हैं लेकिन सभी दल के देता I.N.D.I.A. के लिए नहीं बल्कि अपना चेहरा को ही Focus करते दिख रहे हैं, वैसे में PM Modi का मुकाबला आसान होता दिख रहा है और कांग्रेस के राहुल गाँधी के लिए 2024 का चुनाव चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ मोदी अपने उम्मीदवार की लिस्ट बना रहे हैं वहीं I.N.D.I.A. के दल के संयोजक कौन होगा और किसके चेहरा और रणनीति पर मुहर लगेगा की राजनीति में परेशान है और 26 दल में से कौन दल, कब I.N.D.I.A. से बाहर हो जाये कहना पंडित की भविष्याणि हो जायेगी।

BJP मिशन चंद्रयान-3 के सफलता पर विश्व में ISRO (इसरो) का डंका बजाने में लगी है लेकिन भारत का विपक्ष 2024 में BJP को नहीं PM modi को सत्ता से बेदखल करने के लिए I.N.D.I.A. के नाम से गठबंधन बनाकर देश की जनता का विश्वास जीतना चाहती है लेकिन CAA/NRC, धारा-370, तीन तलाक, UCC, SC#ST एक्ट, श्रीराम मंदिर, काशी कोरिडोर सहित भारत हिन्दू राष्ट्र बनेगा की राजनीति का कूटनीति करता भाजपा के साथ देशवासियों को ज्यादा भरोसा दिखता है। 2014 से 2024 के बीच की बढ़ती महंगाई, बेराजगारी, नोटबंदी जैसे मुद्दे को विपक्ष देशवासियों के बीच चुनावी मुद्दा बनाने में कामयाब होती नहीं दिखी बल्कि कोरोना के संक्रमण काल में Modi ने देश की आवाम का विश्वास जीत लिया है तो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने को भी तैयार है। एक तरफ 38 पाटियों वाला NDA modi-modi का नारा लग रहा है तो दूसरी तरफ 26 पार्टियों वाला *I.N.D.I.A. को एक PM का विश्वासी चेहरा नहीं मिल पा रहा है।* NDA में शामिल ये 38 दल जिसमें 1. भारतीय जनता पार्टी, 2.शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट), 3. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट), 4. राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली), 5. अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, 6. अपना दल (सोनेलाल), 7. नेशनल पीपुल्स पार्टी, 8. नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, 9. ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन,10. सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, 11. मिजो नेशनल फ्रंट, 12. इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, 13. नागा पीपुल्स फ्रंट, नागालैंड, 14. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले), 15. असम गण परिषद, 16. पट्टाली मक्कल काची, 17. तमिल मनीला कांग्रेस, 18. यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल, 19. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, 20. शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त), 21. महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, 22. जननायक जनता पार्टी, 23. प्रहार जनशक्ति पार्टी, 24. राष्ट्रीय समाज पक्ष, 25. जन सुराज्य शक्ति पार्टी, 26. कुकी पीपुल्स एलायंस, 27. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (मेघालय), 28. हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, 29.निषाद पार्टी, 30. अखिल भारतीय एन.आर. कांग्रेस, 31. एचएएम, 32. जन सेना पार्टी,33. हरियाणा लोकहित पार्टी, 34. भारत धर्म जन सेना, 35. केरल कामराज कांग्रेस, 36. पुथिया तमिलगम, 37. लोक जन शक्ति पार्टी (रामविलास पासवन) और 38. गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट शामिल है। 2014 से 2024 के बीच मोदी ने देश में एक से बढ़कर एक बिल को पास करवाया तो अंग्रेजो के बनाये गये कानून भी बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। देश के भीतर भारत माता की जय और जय श्रीराम के जयघोष से युवाओं का दिल जीत चुके हैं वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन में 1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 2. अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), 3. द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक), 4. आम आदमी पार्टी (AAP),5. जनता दल (यूनाइटेड), 6. राष्ट्रीय जनता दल (राजद), 7. झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), 8. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), 9. शिवसेना (यूबीटी), 10. समाजवादी पार्टी (सपा), 11. राष्ट्रीय लोक दल (रालोद), 12. अपना दल (कमेरावादी), 13. जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां), 14. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), 15. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी),16. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), 17. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन,18. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी), 19. ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, 20. मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके), 21. विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके), 22. कोंगुनाडु मक्कल देसिया काची (केएमडीके), 23. मणिथनेय मक्कल काची (एमएमके), 24. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल), 25. केरल कांग्रेस (एम) और 26. केरल कांग्रेस (जोसेफ) शामिल हैं मोदी को 2024 में तीसरी बात PM बनने से रोकना चाहती है लेकिन दोनों गठबंधनों के बीच किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, उनमें YSRCP, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति, बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM), तेलुगु देशम पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जनता दल (सेक्युलर), राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और SAD (मान) शामिल हैं। YSR कांग्रेस पार्टी, जिसने 2019 में आंध्र प्रदेश में चुनाव जीता था और बीजू जनता दल (BJD), जो 2000 से ओडिशा पर शासन कर रही है, दोनों ने संसद में बड़े पैमाने पर BJP के नेतृत्व वाली सरकार के पक्ष में समर्थन किया है। उपरोक्त राजनीतिक दलों के चरित्र से पूरा भारत परिचित है और इन तमाम दलों की लोकप्रियता PM मोदी के सामने कहीं टिकने वाली नहीं है। परिवारवाद-जातिवाद-अपराधवाद-क्षेत्रवाद और आतंकवाद के साथ धर्म पर हो राजनीतिक में भारत की जनता को modi के चेहरा पर भरोसा दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश की जनता बढ़ती बेरोजगारी एवं महंगाई पर चिंतित है लेकिन विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो इन समस्याओं से मुक्ति दिला सके इस वजह से जिन गंभीर समस्याओं पर मोदी ने नियंत्रण किया वह भी हासिये पर न चला जाये इसलिए 2024 में भी मोदी के नाम का डंका बजेगा की विषय पर विचार करते देखे व सुने जाते हैं। 2023 के अंतिम पखवारे में कई महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाला है और NDA और I.N.D.I.A. दोनों को चुनाव जीतना होगा जिससे 2024 के लोकसभा में लाभ होगा। आज भी भारत की जनता को I.N.D.I.A. पर वह भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि गठबंधन अपरिपक्व व नेतृत्व विहीन है।